

Daily करेंट अफेयर्स

» 02 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 गुना बाजार लाभ क्षमता वाली NCDC को 2,000 करोड़ रुपये की 'अनुदान सहायता' योजना को मंजूरी दी।



31 जुलाई 2025 को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹2,000 करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को अनुदान सहायता" को मंजूरी दे दी। यह धनराशि चार वित्तीय वर्षों (2025-26 से 2028-29) में वितरित की जाएगी, जिसमें प्रतिवर्ष ₹500 करोड़ आवंटित किए जाएंगे।

- यह सरकारी वित्त पोषित अनुदान इकिटी समर्थन के रूप में कार्य करता है, जिससे NCDC को खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने में मदद मिलती है - जो कि दस गुना उत्तोलन अनुपात है - जिससे पूरे भारत में सहकारी वित्तपोषण क्षमता का महत्वपूर्ण विस्तार होता है।

- इस योजना का लक्ष्य डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, शीतगृह, श्रम और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों से जुड़ी 13,288 सहकारी समितियों के लगभग 2.9 करोड़ सदस्यों को लाभान्वित करना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच की व्यापक संभावना को दर्शाता है।

- NCDC द्वारा वितरित धनराशि नई परियोजनाओं की स्थापना, संयंत्र विस्तार, तकनीकी

आधुनिकीकरण और संचालन के लिए महत्वपूर्ण कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण में सहायक होगी। इससे सहकारी समितियों को आय-संपत्तियाँ बनाने, तरलता में सुधार और परिचालन निरंतरता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

Key Points:-

(i) एनसीडीसी कार्यान्वयन की देखरेख करेगा—राज्य सरकारों के माध्यम से या सीधे पात्र सहकारी समितियों को ऋण वितरित करेगा जो इसके प्रत्यक्ष वित्तपोषण मानदंडों को पूरा करते हैं। इसकी ज़िम्मेदारियों में कार्यक्रम की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई, निगरानी और वसूली शामिल है।

(ii) अपने अनुशासन के लिए विख्यात, NCDC ने वर्तमान में 99.8% वसूली दर और शून्य गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) कायम रखी हैं, जो प्रभावी रूप से और स्थायी रूप से निधियों का उपयोग करने की इसकी क्षमता को रेखांकित करता है।

(iii) 1963 में स्थापित, NCDC भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता को बढ़ावा देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह अनुदान, सहकारी क्षेत्र के सशक्तिकरण के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, समावेशी विकास, महिला कार्यबल भागीदारी और बुनियादी ढाँचे पर आधारित ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को सुदृढ़ करता है।

2. भारत के वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए PM MITRA योजना के तहत सात नए टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किए गए।



2025 में, भारत सरकार ने तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सात एकीकृत PM मित्र पार्कों की स्थापना में तेज़ी लाकर परिधान और वस्त्र उद्योग में बदलाव लाने के अपने प्रयासों को और मज़बूत किया है। सम्पूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखलाओं को एक ही छत के नीचे समाहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए ये पार्क, बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण, निर्यात में वृद्धि और रोज़गार सृजन के माध्यम से वैश्विक वस्त्र क्षेत्र में अग्रणी बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं।

- अक्टूबर 2021 में स्वीकृत, PM MITRA (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्स्टाइल रीजन एंड अपैरल) पहल का कुल वित्तीय परिव्यय ₹4,445 करोड़ है, जिसे 2021-22 से 2027-28 तक लागू करने की योजना है। पार्कों का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) बनाए जाएंगे। पार्कों के स्थानों का चयन भूमि की उपलब्धता, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे की तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक चुनौती पद्धति पर आधारित था।

- इस योजना से अनुमानित ₹70,000 करोड़ का निजी और विदेशी निवेश आकर्षित होने और लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है। प्रत्येक पार्क से लगभग ₹10,000 करोड़ का निवेश आने और कताई, बुनाई,

रंगाई, प्रसंस्करण और परिधान क्षेत्रों सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में रोज़गार वृद्धि में योगदान देने का अनुमान है। इससे भारत के वस्त्र निर्यात और विनिर्माण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

- केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता में ग्रीनफील्ड पार्कों के लिए ₹500 करोड़ तक और ब्राउनफील्ड पार्कों के लिए ₹200 करोड़ तक की पूंजीगत सहायता शामिल है। प्रत्येक पार्क एंकर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ₹300 करोड़ तक की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (CIS) के लिए भी पात्र होगा। विश्वस्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, डिज़ाइन प्रयोगशालाएँ, इनक्यूबेशन केंद्र, श्रमिक छात्रावास और लॉजिस्टिक्स ज़ोन जैसी सुविधाओं को एकीकृत किया जाएगा।

Key Points:-

(i) ये पार्क भारत की व्यापक कपड़ा रणनीति के अनुरूप हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात करना है। यह पहल SAMARTH (कौशल विकास), SITP (एकीकृत कपड़ा पार्क योजना), वस्त्रों के लिए PLI (उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन) और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) जैसी मौजूदा योजनाओं का पूरक है। यह सरकार के 5F विज़न—खेत से रेशा, कारखाना, फैशन और विदेशी—को भी आगे बढ़ाता है।

(ii) राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन के उदाहरणों में लखनऊ के निकट उत्तर प्रदेश पार्क शामिल है, जो 1,000 एकड़ में फैला है और जिसमें ₹10,000 करोड़ के निवेश और 3 लाख तक रोज़गार सृजन का अनुमान है। मध्य प्रदेश में, धार पार्क को ₹15,000 करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों के साथ 1,550 एकड़ आवंटित किया गया है।

(iii) इन पार्कों की परिकल्पना वैश्विक विनिर्माण केन्द्रों के रूप में की गई है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन और बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए सतत

ऊर्जा उपयोग, उच्च पर्यावरण मानकों और एकीकृत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को शामिल किया जाएगा।

3. ICRISAT ने मानसून मिशन III के तहत छोटे किसानों को सहायता देने के लिए AI-संचालित जलवायु सलाहकार पहल शुरू की।



29-30 जुलाई, 2025 को अपने हैदराबाद मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय आरंभिक कार्यशाला में, अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) ने "बड़े पैमाने पर जलवायु-लचीली कृषि के लिए AI-संचालित संदर्भ-विशिष्ट कृषि-मौसम परामर्श सेवाएँ" नामक एक ऐतिहासिक पहल का अनावरण किया। भारत सरकार के मानसून मिशन III के तहत समर्थित, इस परियोजना का उद्देश्य उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) उपकरणों का उपयोग करके लाखों छोटे किसानों को अति-स्थानीय, समय पर और कार्रवाई योग्य जलवायु सलाह प्रदान करना है ताकि बिगड़ती जलवायु परिवर्तनशीलता के सामने लचीलापन बढ़ाया जा सके।

• यह पहल एक शक्तिशाली बहु-संस्थागत संघ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें ICRISAT; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-CRIDA); अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान (ILRI); और

तकनीकी साझेदार जैसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IIITM), भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), CSIR-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (CSIO), IIT रोपड़ (AI फॉर एग्री एक्सीलेंस सेंटर) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) शामिल हैं।

• नई सेवा का केंद्र iSAT (इंटेलिजेंट सिस्टम्स एडवाइजरी टूल) है, जिसे शुरुआत में मानसून मिशन II के तहत कृषि-मौसम संबंधी आंकड़ों को व्यावहारिक सलाह में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अब इस प्लेटफॉर्म को मशीन लर्निंग-आधारित फसल मौसम मॉडल, उपग्रह विश्लेषण और निर्णय-वृक्ष ढाँचों के साथ उन्नत किया गया है ताकि बुवाई, सिंचाई और कीट नियंत्रण जैसे प्रमुख कृषि निर्णयों के लिए व्यक्तिगत सुझाव तैयार किए जा सकें।

• सलाह सहज, कम बैंडविड्थ वाले डिजिटल चैनलों के ज़रिए प्रसारित की जाती है—खासकर एक एआई-संचालित व्हाट्सएप बॉट जो क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, साथ ही एसएमएस संदेश और ग्राम संसाधन केंद्र इंटरफेस भी। यह अंतिम-मील डिज़ाइन यह सुनिश्चित करता है कि दूर-दराज और डिजिटल रूप से वंचित किसानों को भी मौसम और प्रबंधन संबंधी उपयोगी अलर्ट मिलें।

Key Points:-

(i) महाराष्ट्र में पहले चरण का कार्यान्वयन पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें छोटे किसानों तक पहुँचने के लिए ICAR की कृषि-मौसम विज्ञान क्षेत्र इकाइयों (AMFUs) का लाभ उठाया जा रहा है। पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभव एक नियोजित राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेंगे और वैश्विक दक्षिण के जलवायु-तनावग्रस्त क्षेत्रों में इसी तरह के समाधानों के लिए एक वैश्विक खाका तैयार करेंगे।

(ii) पूर्व पायलट परिनियोजनों के दौरान, iSAT परामर्शों से प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हुए हैं—

लगभग 80% किसान संतुष्ट, 75% से अधिक पूर्वानुमान सटीकता, और कुछ फसलों में 16% तक उपज में सुधार। उन्नत AI मॉडल से 12 करोड़ से अधिक छोटे किसानों में अनुकूली कृषि निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे अर्ध-शुष्क भू-भागों में जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

(iii) यह पहल भारत के व्यापक डिजिटल कृषि, जलवायु परिवर्तन और नवाचार ढाँचों, जिनमें मानसून मिशन III, आत्मनिर्भर भारत और विकासशील मौसमजीपीटी प्लेटफॉर्म शामिल हैं, के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। स्वदेशी तकनीक और अंतर-संस्थागत सहयोग का लाभ उठाते हुए, यह भारत के स्केलेबल जलवायु-स्मार्ट कृषि समाधानों में अग्रणी के रूप में उभरने का संकेत देता है।

4. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के DPA में 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया।



31 जुलाई 2025 को, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के प्रमुख हैं, ने गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण (DPA) में भारत के पहले मेक-इन-इंडिया 1 मेगावाट (MW) ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। यह परियोजना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के साथ

संरक्षित है और 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- यह नव-उद्घाटित संयंत्र भारत में पहली हरित हाइड्रोजन सुविधा है, जिसे पूरी तरह से मेक-इन-इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है, जो टिकाऊ और स्वदेशी हरित ऊर्जा अवसंरचना के निर्माण में देश की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह संयंत्र सालाना 140 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जो बंदरगाहों के कार्बन-मुक्तिकरण और स्वच्छ ईंधन अपनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

- इस परियोजना को चेन्नई, तमिलनाडु स्थित एक प्रमुख भारतीय इंजीनियरिंग फर्म, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) लिमिटेड के इंजीनियरिंग सहयोग से विकसित किया गया है। यह भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- उद्घाटन समारोह में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें शामिल थे - शांतनु ठाकुर, राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय; टी.के. रामचंद्रन, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव; और सुशील कुमार सिंह, DPA के अध्यक्ष, तथा जल शक्ति मंत्रालय, DPA और L&T के वरिष्ठ अधिकारी।

Key Points:-

(i) यह हरित हाइड्रोजन संयंत्र भारत द्वारा अपने बंदरगाहों पर पर्यावरण-अनुकूल पहलों को लागू करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इससे पहले, डीपीए ने देश के पहले मेक-इन-इंडिया पूर्ण-इलेक्ट्रिक हरित टग का निर्माण शुरू किया था, जिससे मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के तहत हरित परिवर्तन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और पुष्ट हुई।

(ii) इस एक मेगावाट संयंत्र की स्थापना स्वदेशी नवाचार के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनने के भारत के लक्ष्य को रेखांकित करती है। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय मिशनों

का समर्थन करती है और भविष्य के लिए तैयार, टिकाऊ बंदरगाह अवसंरचना का निर्माण करके विकसित भारत@2047 में योगदान देती है।

(iii) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) को भारत सरकार ने जनवरी 2023 में ₹19,744 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी। इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, साथ ही तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करना है। NGHM भारत के कार्बन-मुक्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक केंद्रीय स्तंभ है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 जैसी व्यापक पहलों के साथ संरेखित है।

BANKING & FINANCE

1. बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 शासन, लेखा परीक्षा पारदर्शिता और जमाकर्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए 1 अगस्त से लागू हो गया।



बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025, जिसे 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था, प्रमुख प्रावधानों के लागू होने के साथ 1 अगस्त 2025 से

प्रभावी हो गया। यह ऐतिहासिक कानून पाँच प्रमुख बैंकिंग कानूनों—जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 शामिल हैं—में 19 सुधारों के माध्यम से संशोधन करता है, जिनका उद्देश्य सुदृढ़ शासन, जमाकर्ताओं की सुरक्षा, लेखा परीक्षा पारदर्शिता और सहकारी बैंकों को संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप बनाना है।

● अधिनियम में निदेशक पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त 'पर्याप्त हित' की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया गया है, जिसमें सीमा को 5 लाख रुपये (1968 से अपरिवर्तित) से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आधुनिक वित्तीय वास्तविकताओं के बीच केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हितधारक ही बैंकिंग प्रशासन को प्रभावित करें।

● 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप, सहकारी बैंकों में गैर-कार्यकारी निदेशकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) का अधिकतम कार्यकाल 8 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, जिससे इन सदस्य-संचालित संस्थाओं में निरंतरता और बेहतर निगरानी को बढ़ावा मिलेगा।

Key Points:-

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को अब बिना दावे वाले शेयरों, ब्याज और बॉन्ड मोचन राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित करने की अनुमति मिल गई है। इससे बैंकिंग मानदंड कंपनी अधिनियम के अनुरूप हो गए हैं, जिससे निवेशकों की सुरक्षा और निष्क्रिय परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हुआ है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक निर्धारित करने का नया अधिकार दिया गया है, जिससे वे शीर्ष स्तरीय लेखा परीक्षा पेशेवरों को नियुक्त कर सकेंगे और लेखा परीक्षा की स्वतंत्रता और पारदर्शिता में सुधार कर सकेंगे, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों में सुधार

होने की उम्मीद है।

2. CEF ग्रुप ने दो संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्रों के निर्माण के लिए जर्मन निर्यात वित्त बैंक से 38 मिलियन यूरो प्राप्त किए।



1 अगस्त 2025 को, जर्मन एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक (एक सरकारी समर्थित निर्यात ऋण एजेंसी - ECA) ने भारत के एक क्लीनटेक स्टार्टअप, CEF ग्रुप को मिश्रित इक्विटी और ऋण वित्तपोषण में €38 मिलियन (लगभग ₹345 करोड़) की मंजूरी दी। यह रणनीतिक वित्तपोषण भारत के स्वच्छ ऊर्जा अभियान के तहत संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्रों के विकास को बढ़ावा देगा।

● 38 मिलियन यूरो की यह धनराशि CEF ग्रुप (स्वच्छ ऊर्जा ईंधन समूह) द्वारा दो संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्रों के विकास के लिए वित्तपोषित की जाएगी। ये संयंत्र भारत भर में 22 CBG इकाइयाँ स्थापित करने, कृषि अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW), और औद्योगिक अवशेषों को स्वच्छ, नवीकरणीय गैस में परिवर्तित करने के सीईएफ के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं।

● 2018 में स्थापित, CEF समूह, SATAT योजना (सस्ती परिवहन के लिए सतत विकल्प) के अनुरूप कार्य करता है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा हरित परिवहन ईंधन के

रूप में CBG के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है।

● CEF के पास वर्तमान में तीन परियोजनाएँ चल रही हैं जो लगभग पूरी होने वाली हैं: जम्मू और अहमदाबाद में दो MSW (नगरीय ठोस अपशिष्ट) आधारित संयंत्र, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रेस-मड आधारित संयंत्र। प्रेस-मड चीनी मिलों का एक उपोत्पाद है। नए वित्तपोषण से अगले दो बायोगैस संयंत्रों का निर्माण तेज़ी से हो सकेगा।

Key Points:-

(i) यह परियोजना जैविक कचरे को CBG, अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन (RDF) और जैविक खाद जैसे मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करके चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। ये बायोगैस संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करेंगे, किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करेंगे, मीथेन उत्सर्जन को कम करेंगे और भारत की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेंगे।

(ii) यह जलवायु वित्त के क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच एक ऐतिहासिक सीमा-पार साझेदारी का प्रतीक है। जर्मन निर्यात वित्त बैंक जैसी निर्यात ऋण एजेंसियों (ECAs) की भूमिका स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करती है और वैश्विक दक्षिण में स्थायी ऊर्जा अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) को बढ़ावा देती है।

ECONOMY & BUSINESS

1. जुलाई 2025 में GST संग्रह ₹1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन शुद्ध वृद्धि तेजी से धीमी होकर 1.7% हो गई।



जुलाई 2025 में, भारत की वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली ने लगभग ₹1.96 लाख करोड़ का रिकॉर्ड सकल संग्रह प्राप्त किया, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, स्थिर घरेलू खपत और आयात गतिविधि को दर्शाते हुए, साल-दर-साल 7.5% की स्थिर वृद्धि दर्शाता है। हालाँकि, रिफंड में तीव्र वृद्धि ने विकास को धीमा कर दिया, जिससे शुद्ध GST राजस्व केवल ₹1.69 लाख करोड़ रह गया, जो जुलाई 2024 से केवल 1.7% की मामूली वृद्धि है।

- जुलाई 2025 में भारत का सकल GST राजस्व ₹1.95-1.96 लाख करोड़ रहा, जो एक साल पहले ₹1.82 लाख करोड़ था। जहाँ मुख्य संग्रह संकेतक में 7.5% की वृद्धि हुई, वहीं शुद्ध प्राप्ति—₹27,147 करोड़ के रिफंड के बाद—केवल 1.7% बढ़कर ₹1.69 लाख करोड़ हो गई, जो इस बात पर ज़ोर देता है कि संग्रह का एक बड़ा हिस्सा करदाताओं को वापस कर दिया गया।

- घरेलू GST राजस्व में 6.7% की मामूली वृद्धि हुई, जो कुल मिलाकर लगभग ₹1.43 लाख करोड़ रहा, जबकि आयात पर GST पिछले वर्ष की तुलना में 9.5% बढ़कर ₹52,712 करोड़ तक पहुँच गया। आयात की मात्रा में वृद्धि और आयातित वस्तुओं की बढ़ती खपत के कारण ऐसा हुआ। उल्लेखनीय रूप से, घरेलू स्रोतों से शुद्ध राजस्व में मामूली गिरावट देखी गई, जो बढ़ते रिफंड दावों के बीच आंतरिक

मांग में कमी या अनुपालन संबंधी समस्याओं की ओर इशारा करती है।

Key Points:-

(i) कुल संग्रह में, IGST का सबसे बड़ा हिस्सा रहा—लगभग ₹1.03 लाख करोड़, उसके बाद SGST ₹44,059 करोड़, CGST ₹35,470 करोड़ और क्षतिपूर्ति उपकर लगभग ₹12,670 करोड़ रहा। रिफंड बहिर्वाह में 66.8% की वृद्धि हुई, जो पहले के रुझानों के अनुरूप है और संभवतः अत्यधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट, उलटे शुल्क ढांचे या प्रक्रियात्मक समय प्रभावों के कारण हुआ। इस बेमेल का शुद्ध प्राप्तियों पर भारी असर पड़ा।

(ii) अप्रैल-जुलाई 2025 की अवधि के लिए, सकल GST संग्रह ₹8.18 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.7% अधिक है, जबकि शुद्ध संग्रह ₹7.11 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.4% अधिक है। हालाँकि संचयी आँकड़े निरंतर राजकोषीय मजबूती का संकेत देते हैं, शुद्ध वृद्धि दर में गिरावट एक राजकोषीय चेतावनी के रूप में उभर रही है, खासकर यदि रिफंड का रुझान दूसरी छमाही तक जारी रहता है।

(iii) राज्यवार रुझान असमान प्रदर्शन दर्शाते हैं—मध्य प्रदेश (+18%), आंध्र प्रदेश (+14%), और बिहार (+16%) ने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की, जबकि महाराष्ट्र (+6%), कर्नाटक और तमिलनाडु (+7-8%) में धीमी गति देखी गई। तेलंगाना, दिल्ली और गुजरात ने कम एकल अंकों में मामूली वृद्धि दर्ज की। नकारात्मक पक्ष पर, मणिपुर (-36%), मिज़ोरम (-21%), और झारखंड (-3%) जैसे राज्यों में भारी गिरावट आई—जिससे अंतर-राज्यीय अनुपालन और आर्थिक विचलन के गहन विश्लेषण की आवश्यकता पर बल मिलता है।

MOUs and Agreement

1. DPIIT ने आवास और स्वास्थ्य सेवा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए HDFC कैपिटल और Roche इंडिया के साथ दो प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।



31 जुलाई 2025 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoC&I) के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड और रोश इंडिया के साथ दो प्रमुख समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य भारत में किफायती आवास, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी (PropTech) और स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। ये साझेदारियाँ आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 जैसे राष्ट्रीय दृष्टिकोणों के अनुरूप हैं।

● DPIIT ने किफायती आवास और PropTech क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, HDFC बैंक की सहायक कंपनी HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के शहरी रियल एस्टेट विकास परिदृश्य में लागत-प्रभावी, तकनीक-संचालित समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए, DPIIT के निदेशक मोहम्मद इशारार अली और HDFC कैपिटल के CEO विपुल रूंगटा ने इस समझौता ज्ञापन पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए।

● यह समझौता ज्ञापन HDFC कैपिटल की प्रमुख पहल - H@ART कार्यक्रम (HDFC अफोर्डेबल रियल एस्टेट एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम) पर केंद्रित है - जिसका उद्देश्य प्रॉपर्टेक स्टार्टअप्स को समर्थन देकर और उन्हें डेवलपर्स, निवेशकों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ जोड़कर आवास विकास मूल्य श्रृंखला में दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना और स्केलेबिलिटी को बढ़ावा देना है।

● 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत@2047' के राष्ट्रीय मिशनों के अनुरूप, साझेदारी का उद्देश्य सतत नवाचार को उत्प्रेरित करना और त्वरक, मेंटरशिप कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे और आवास क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाले नेटवर्क तक पहुंच के माध्यम से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

Key Points:-

(i) उसी दिन, DPIIT ने भारत के स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए स्विट्जरलैंड स्थित रोश समूह की सहायक कंपनी, Roche प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (Roche इंडिया) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर DPIIT के निदेशक डॉ. सुमीत जारंगल और रोश इंडिया के प्रबंध निदेशक राजविंदर मेहदवान ने हस्ताक्षर किए।

(ii) DPIIT-Roche इंडिया समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेत्र विज्ञान, रुधिर विज्ञान और दुर्लभ रोगों जैसे चिकित्सीय क्षेत्रों में DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान करना है। यह सहयोग स्टार्टअप्स को Roche की विशेषज्ञता, वैश्विक मार्गदर्शन, उन्नत बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार एवं पायलट सत्यापन हेतु प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करेगा।

(iii) दोनों समझौता ज्ञापन प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार-संचालित विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। जहाँ HDFC साझेदारी शहरी और आवास

प्रौद्योगिकी पहलों को बढ़ावा देती है, वहीं रोश सहयोग महत्वपूर्ण चिकित्सीय क्षेत्रों में लक्षित स्टार्टअप समर्थन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा नवाचार और क्षमता निर्माण को मज़बूत करता है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. डॉ. मयंक शर्मा ने 1 अगस्त 2025 से रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) के रूप में पदभार ग्रहण किया।



1 अगस्त 2025 को, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएस) के 1989 बैच के प्रतिष्ठित अधिकारी डॉ. मयंक शर्मा को औपचारिक रूप से नया वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) (एफए(डीएस)) नियुक्त किया। उनका कार्यकाल रक्षा लेखा और शासन में उनके समृद्ध करियर का परिणाम है, जिसमें रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) के रूप में उनकी हालिया भूमिका भी शामिल है।

● अपनी नई भूमिका में, डॉ. शर्मा भारत के सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक के रणनीतिक CFO बन गए हैं, जो सेना, नौसेना, वायु सेना और DRDO, MES और तटरक्षक बल जैसे रक्षा संगठनों को वित्तीय सलाह और सहमति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

● एकीकृत वित्तीय सलाहकार प्रणाली के अनुसार, वह बजट अनुमानों, व्यय प्रस्तावों की देखरेख करेंगे

और पूंजीगत एवं राजस्व आवंटन में वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। वित्त वर्ष 2025-26 में ₹6 लाख करोड़ को पार करने वाले रक्षा बजट के प्रबंधन में उनका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है।

● FA(DS) का पदभार ग्रहण करने से पहले, डॉ. शर्मा ने रक्षा लेखा विभाग में सीजीडीए के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने सभी सैन्य इकाइयों में वेतन, पेंशन, लेखा परीक्षा और वित्तीय डिजिटलीकरण पहलों का पर्यवेक्षण किया। उनका कार्यकाल रक्षा मंत्रालय में प्रणालीगत सुधारों और वित्तीय जवाबदेही ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए जाना जाता है।

Key Points:-

(i) डॉ. शर्मा ने कैबिनेट सचिवालय में क्रमशः अवर सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। इन भूमिकाओं ने उन्हें नीति-निर्माण, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और रणनीतिक शासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है—ये कौशल रक्षा अधिग्रहण और पूंजीगत परियोजनाओं में वित्त और निर्णय-प्रक्रिया को एकीकृत करने के लिए उनकी सलाहकार भूमिका में उपयोगी साबित होंगे।

(ii) एक अनुभवी राजनयिक, डॉ. शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC), संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण आयोग और UNCITRAL में वैकल्पिक स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र के अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है, जिनमें दिल्ली नगर निगम (MCD) के अतिरिक्त आयुक्त और एम्स, नई दिल्ली में वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार के पद शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के जटिल संगठनों के प्रबंधन की उनकी क्षमता को दर्शाता है।

(iii) डॉ. शर्मा ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पदभार ग्रहण कर रहे हैं जब भारत रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) के तहत रक्षा खरीद में तेज़ी ला रहा है, स्वदेशी

सोर्सिंग के लिए GeM और SRIJAN जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार कर रहा है, और वित्तीय सुधारों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को प्राथमिकता दे रहा है। उनकी नियुक्ति रक्षा आधुनिकीकरण में वित्तीय विवेक, पारदर्शिता और लागत-प्रभावशीलता पर सरकार के ध्यान का संकेत देती है।

2. वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने 47वें नौसेना उप प्रमुख (VCNS) के रूप में कार्यभार संभाला।



वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, AVSM, NM ने 01 अगस्त 2025 को आधिकारिक तौर पर नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख (VCNS) के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को सम्मानित किया।

● वाइस एडमिरल वात्सायन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), पुणे के 71वें पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र हैं और उन्हें 01 जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था। गनरी और मिसाइल सिस्टम के विशेषज्ञ, उन्होंने तीन दशकों से अधिक के अपने नौसैनिक करियर में विभिन्न कमांड, ऑपरेशनल और रणनीतिक स्टाफ भूमिकाएँ निभाई हैं।

● अपने समुद्री कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर सेवा की, जिनमें निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS मैसूर, INS निशंक और तटरक्षक बल के OPV ICGS संग्राम के कमीशनिंग दल का हिस्सा होना शामिल है। उन्होंने INS मैसूर के कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया और सी-05, INS विभूति, INS नाशक, आईएनएस कुठार और INS सहाद्री जैसे जहाजों की कमान संभाली, जिनमें से अंतिम कमीशनिंग कमांडिंग ऑफिसर के रूप में थे।

● फरवरी 2020 में, उन्होंने पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला और गलवान झड़पों के बाद बढ़ी हुई समुद्री सुरक्षा के बीच प्रमुख परिचालन तैनाती और अभ्यासों की देखरेख की। संवेदनशील समय के दौरान पूर्वी बेड़े की तैयारियों को आकार देने में उनके नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Key Points:-

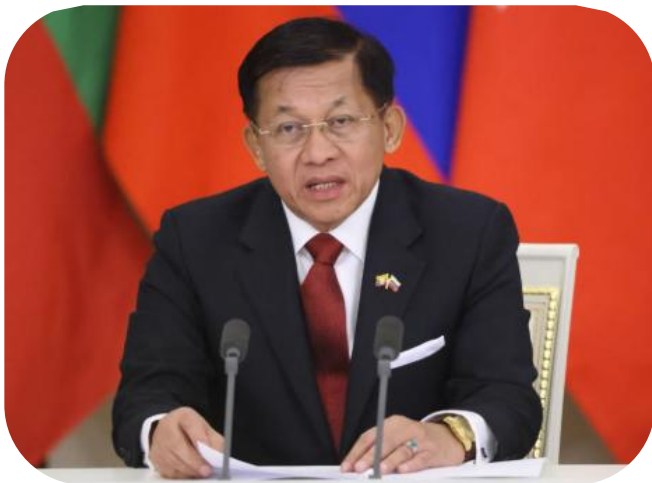
(i) वाइस एडमिरल वात्सायन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (वेलिंगटन), नेवल वॉर कॉलेज (गोवा) और नेशनल डिफेंस कॉलेज (नई दिल्ली) से स्नातक हैं। उन्होंने नौसेना मुख्यालय में संयुक्त निदेशक और कार्मिक निदेशक (नीति), नौसेना योजना निदेशक (परिप्रेक्ष्य योजना) और प्रधान नौसेना योजना निदेशक सहित कई उच्च-स्तरीय पदों पर कार्य किया है।

(ii) फरवरी 2018 में फ्लैग रैंक पर पदोन्नति के बाद, उन्होंने सहायक नौसेनाध्यक्ष (नीति एवं योजना) के रूप में कार्य किया और बाद में पूर्वी बेड़े का नेतृत्व किया। असाधारण सेवा के लिए उन्हें 2021 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उप कमांडेंट और बाद में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने, जहाँ उन्होंने परिचालन तत्परता और बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया।

(iii) अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले, वे एकीकृत रक्षा

स्टाफ (DCIDS) के उप-प्रमुख - संचालन और बाद में IDS मुख्यालय में DCIDS (नीति, योजना और बल विकास) के पद पर कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने संयुक्त अभियानों, एकीकरण, नीति निर्माण और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका विवाह सरिता से हुआ है और उनके दो बच्चे हैं—एक बेटा जो अर्थशास्त्र में स्नातक है और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA है, और एक बेटी जिसने मानविकी में अपनी पढ़ाई पूरी की है।

3. म्यांमार में नई अंतरिम-संघीय सरकार का गठन हुआ और यू न्यो साव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तथा आपातकाल आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया।



जुलाई 2025 में, म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद (NDSC) ने आधिकारिक तौर पर एक नई अंतरिम-संघ सरकार के गठन की घोषणा की, साथ ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति आयोग के गठन की भी घोषणा की, जो रक्षा का प्रबंधन करेगा और वर्ष के अंत में होने वाले आम चुनावों की तैयारियों की देखरेख करेगा।

● यू न्यो साव को म्यांमार का 13वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और वे नवगठित अंतरिम-संघीय सरकार का नेतृत्व करेंगे। उनकी नियुक्ति म्यांमार के तख्तापलट के बाद के प्रशासनिक ढाँचे

में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य संवैधानिक प्रक्रियाओं को बहाल करना है।

● सैन्य जुंटा के अनुसार, वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाईंग राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति आयोग के प्रमुख होंगे। वे म्यांमार की सशस्त्र सेनाओं के कार्यवाहक राष्ट्रपति और कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्य करते रहेंगे और प्रमुख सुरक्षा एवं सैन्य कार्यों पर वास्तविक नियंत्रण बनाए रखेंगे।

Key Points:-

(i) राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद (NDSC), जिसका गठन मूल रूप से सैन्य तख्तापलट के बाद फरवरी 2021 में किया गया था, ने अब अपनी भूमिका का विस्तार करते हुए चुनाव प्रबंधन और शांति निगरानी को भी इसमें शामिल कर लिया है। यह कदम लोकतांत्रिक बहाली पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के बीच उठाया गया है।

(ii) इस घोषणा के साथ, म्यांमार की सैन्य सरकार ने चार साल से अधिक समय से लागू आपातकाल को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। यह आपातकाल पहली बार फरवरी 2021 में घोषित किया गया था, जब सेना ने आंग सान सू की के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था।

(iii) इसके अतिरिक्त, NDSC ने 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसने संप्रभु शक्तियों को कमांडर-इन-चीफ को हस्तांतरित कर दिया था और खुद को भंग कर दिया है, जिससे विस्तारित सैन्य नियंत्रण को वापस लेने और दिसंबर 2025 तक नागरिक चुनावों की तैयारी शुरू करने का संकेत मिलता है।

4. शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।



31 जुलाई 2025 को, 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी शशिप्रकाश गोयल ने आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे उसी दिन सेवानिवृत्त हुए मनोज कुमार सिंह का स्थान लेंगे। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्रशासनिक निरंतरता और तीव्र विकास एजेंडे को पुष्ट करती है।

- गोयल ने आठ वर्षों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया और नागरिक उड्डयन, संपदा और प्रोटोकॉल जैसे विभागों का कार्यभार संभाला। उन्हें मुख्यमंत्री के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक के रूप में जाना जाता है, जो नीतिगत सुसंगतता और स्थिर शासन सुनिश्चित करते हैं।

- अपने पूरे कार्यकाल में, गोयल ने मथुरा, इटावा, प्रयागराज और देवरिया के ज़िला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त रेजिडेंट कमिश्नर और केंद्र में उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। ये भूमिकाएँ उनकी बहुमुखी प्रतिभा और शासन की गहराई को उजागर करती हैं।

Key Points:-

(i) उत्तर प्रदेश के शीर्ष नौकरशाह के रूप में, गोयल प्रमुख निकायों की भी देखरेख करेंगे: बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC), PICUP के

अध्यक्ष, UPEIDA और UPSHA के CEO, यूपी DASP के परियोजना निदेशक और समन्वय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव।

(ii) पदभार ग्रहण करते ही, गोयल ने औद्योगिक विकास को गति देते हुए "शून्य सहनशीलता और शून्य भ्रष्टाचार" की नीतियों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और व्यापार सुगमता में वृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने पर ज़ोर दिया।

(iii) शशिप्रकाश गोयल ने राज्य के अनुरोध के बावजूद अपने पूर्ववर्ती मनोज कुमार सिंह का कार्यकाल न बढ़ाने के केंद्र के फैसले के बाद कार्यभार संभाला है। गोयल के जनवरी 2027 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहने की उम्मीद है, जिससे उन्हें राज्य की नौकरशाही पर अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए लगभग 18 महीने का समय मिलेगा।

AWARDS

1. 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 घोषित: 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को पहला राष्ट्रीय सम्मान मिला।



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 1 अगस्त

2025 को की गई। ये पुरस्कार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के बीच प्रमाणित फिल्मों के लिए भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, फीचर, गैर-फीचर, लेखन और नई AVGC श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। यह आयोजन देश भर की कहानी कहने की कला और सिनेमाई विविधता का एक महत्वपूर्ण उत्सव था।

- पुरस्कार चयन प्रक्रिया में 332 फीचर फिल्मों, 115 गैर-फीचर फिल्मों, 27 पुस्तकें और 16 फिल्म समीक्षाएं शामिल थीं। फीचर फिल्म श्रेणी के लिए जूरी अध्यक्ष प्रसिद्ध फिल्मकार अशुतोष गोवारिकर थे, जबकि गैर-फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व कन्नड़ निर्देशक पी. शेषाद्रि ने किया। चयन प्रक्रिया ने भारत की विभिन्न भाषाओं और शैलियों की फिल्मों की कलात्मक गुणवत्ता और सामाजिक योगदान को मान्यता दी।

- सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल को मिला, जिसे विधु विनोद चोपड़ा ने निर्देशित किया। इस फिल्म को स्वर्ण कमल और ₹3 लाख की राशि से सम्मानित किया गया। फिल्म में समाज के वंचित वर्ग के युवाओं द्वारा यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी में झेली जाने वाली कठिनाइयों को सजीव और यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया।

- शाहरुख खान को उनके करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, जो विक्रान्त मैसी के साथ साझा किया गया। शाहरुख को जवान में उनके दोहरे अभिनय के लिए सम्मानित किया गया, जबकि विक्रान्त को 12वीं फेल में संवेदनशील और प्रेरणादायक भूमिका के लिए यह पुरस्कार मिला। यह संयुक्त सम्मान व्यवसायिक और विषय आधारित सिनेमा के बीच संतुलन का उदाहरण बना।

Key Points:-

(i) रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में एक प्रवासी मां की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का

पुरस्कार मिला। यह उनके तीन दशक के फिल्मी करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। उनकी भूमिका को भावनात्मक गहराई और सामाजिक विषय की वजह से काफी सराहना मिली।

(ii) सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी (हिंदी) के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार और स्वर्ण कमल मिला। करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार मिला। इस बार पहली बार जोड़ी गई AVGC श्रेणी में हनु-मन (तेलुगु) को सर्वश्रेष्ठ एवीजीसी फिल्म का पुरस्कार मिला।

(iii) क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को भी प्रमुख पहचान मिली, जिनमें उल्लोजुकू (मलयालम) और पार्किंग (तमिल) को उनकी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। उर्वशी और जानकी बोडीवाला को सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। गैर-फीचर श्रेणी में फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म और गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री घोषित किया गया। सैम बहादुर, एनिमल और पूककालम जैसी फिल्मों को संगीत, नृत्य निर्देशन और सामाजिक संदेश जैसे क्षेत्रों में विशेष उल्लेख प्राप्त हुआ।

IMPORTANT DAYS

1. भारत तीन तलाक कानून की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1 अगस्त 2025 को छठा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया।



मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, जिसे 'मुस्लिम महिला अधिकार दिवस' के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस कानून ने एक बार में तीन तलाक देने की प्रथा को अपराध घोषित कर दिया और मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और समानता का अधिकार दिया। 2025 में मनाया जाने वाला यह दिवस इस ऐतिहासिक कानून की छठी वर्षगांठ है।

- यह दिवस 1 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित 2019 अधिनियम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसने एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को एक दंडनीय आपराधिक अपराध बना दिया।

- तीन तलाक, एक त्वरित तलाक पद्धति है जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष तीन बार "तलाक" कहकर अपनी पत्नी को एकतरफा तलाक दे सकता है, 2019 के अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित होने से पहले कानूनी रूप से प्रचलित था।

- इस अधिनियम ने मुस्लिम महिलाओं को एकतरफा तलाक और कानूनी सहारा से सुरक्षा प्रदान की, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के ढांचे के भीतर लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

Key Points:-

(i) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (MoMA) ने 2020 में घोषणा की थी कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के सम्मान और जागरूकता फैलाने के लिए 1 अगस्त को प्रतिवर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

(ii) पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त 2020 को, इस कानून की पहली वर्षगांठ पर मनाया गया था, और इसे सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता रहा है।

2. राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025, डॉ. बी.सी. रॉय के सम्मान में तथा चिकित्सकों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकाश डालने के लिए 1 जुलाई को मनाया गया।



भारत ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 मनाया, जो एक महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्र निर्माण और जन स्वास्थ्य में डॉक्टरों की अमूल्य भूमिका को मान्यता देता है, साथ ही इस वर्ष उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1991 से प्रतिवर्ष 1 जुलाई को डॉ. बी.सी. रॉय (1882-1962) की स्मृति में मनाया जाता है, जो भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी और भारत रत्न से सम्मानित थे।

● 2025 का विषय— "मुखौटे के पीछे: चिकित्सकों का उपचार कौन करता है?"—डॉक्टरों के लिए मानसिक और भावनात्मक समर्थन के महत्व पर जोर देता है, जिसमें थकान और मनोवैज्ञानिक तनाव पर प्रकाश डाला गया है।

Key Points:-

- (i) यह दिन विशेष रूप से जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान, जीवन बचाने में डॉक्टरों के समर्पण का सम्मान करता है और उनकी सेवा के लिए सामाजिक कृतज्ञता को बढ़ावा देता है।
- (ii) पूरे भारत में आयोजित कार्यक्रमों में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच अभियान और भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) तथा अस्पतालों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह शामिल थे।
- (iii) यह दिवस पूरे भारत में चिकित्सा पेशेवरों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और बेहतर कार्य स्थितियों की वकालत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

3. लौंग सिंड्रोम जागरूकता दिवस 2025 - दुर्लभ लौंग विकार समुदाय का समर्थन करने के लिए 3 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।



हर साल 3 अगस्त को, दुनिया भर में क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है ताकि क्लोव्स

सिंड्रोम—एक दुर्लभ जन्मजात अतिवृद्धि विकार—के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2010 में पहली बार शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य इस बीमारी से प्रभावित दुनिया भर के अनुमानित 200 से कम लोगों के लिए शीघ्र निदान, अनुसंधान, उपचार तक पहुँच और सहायता को बढ़ावा देना है।

● CLOVES का अर्थ है: Congenital Lipomatous Overgrowth, Vascular Malformations, Epidermal Nevi, और Skeletal/Spinal anomalies। यह रोग जन्म के समय से ही वसा ऊतक की अधिकता, त्वचा पर जन्म चिह्न, रक्त या लसीका वाहिकाओं की खराबी और रीढ़ की हड्डी या हड्डियों की विकृति का कारण बनता है।

● लौंग दैहिक उत्परिवर्तनों से उत्पन्न होता है—अक्सर प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान PIK3CA जीन में—जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित कोशिकाओं का एक मोज़ेक पैटर्न बनता है। चूँकि ये जीन परिवर्तन रोगाणु कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करते, इसलिए लौंग वंशानुगत नहीं है, और आमतौर पर माता-पिता से बच्चे में जाने के बजाय अनियमित रूप से होता है।

● चूँकि क्लोव्स बहुत दुर्लभ है और लक्षणों में भिन्नता बहुत अधिक है, इसलिए कई मामलों का पता नहीं चल पाता या उनका गलत निदान हो जाता है—अक्सर प्रोटियस सिंड्रोम या क्लिपेल-ट्रेनाउने जैसी स्थितियों के रूप में। जागरूकता से रोग का शीघ्र पता लगाने, सिरोलिमस और स्क्लेरोथेरेपी जैसे उपायों तक पहुँच और विल्म्स ट्यूमर जैसी जटिलताओं की नियमित निगरानी में मदद मिलती है।

Key Points:-

- (i) प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिवस सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा देता है, कलंक का मुकाबला करता है, चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है, CLOVES से प्रभावित परिवारों

को जोड़ता है, तथा लक्षण प्रबंधन और जीवन-वर्धक उपचारों के लिए धन मुहैया कराता है।

(ii) समर्थक #ClovesSyndromeAwarenessDay जैसे हैशटैग का उपयोग करके सोशल मीडिया अभियानों, वर्चुअल और व्यक्तिगत धन उगाहने, सामुदायिक कहानी सुनाने और शैक्षिक वेबिनार आयोजित करके सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। क्लोव्स सिंड्रोम कम्युनिटी, जो रेयर ऐज़ वन नेटवर्क का एक हिस्सा है, मरीजों, चिकित्सा टीमों और शोधकर्ताओं को एकजुट करने के लिए समन्वित वार्षिक अभियान चलाता है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. भारतीय नौसेना को कोलकाता में GRSE से तीसरा प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट 'INS हिमगिरी' प्राप्त हुआ।



31 जुलाई 2025 को, भारतीय नौसेना (IN) को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) से प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट, INS हिमगिरी (यार्ड 3022) प्राप्त हुआ। जहाज को आधिकारिक तौर पर कोलकाता, पश्चिम बंगाल में सौंपा गया।

● INS हिमगिरि, भारतीय नौसेना के लिए GRSE द्वारा निर्मित नीलगिरि-श्रेणी (प्रोजेक्ट 17A) स्टील्थ फ्रिगेट्स का तीसरा युद्धपोत है। प्रोजेक्ट 17ए, प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक-श्रेणी) का अनुवर्ती है और

भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अपने नौसैनिक बेड़े का आधुनिकीकरण करना है।

● भारतीय नौसेना की ओर से पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी (तकनीकी) रियर एडमिरल रवनीश सेठ ने इस जहाज को स्वीकार किया। इस औपचारिक हस्तांतरण से नौसेना की आधुनिकीकरण पहल के तहत उसकी सतही लड़ाकू क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा मिला है।

● इस पोत का निर्माण परियोजना 17A के तहत तीन स्टील्थ फ्रिगेट के निर्माण हेतु GRSE को दिए गए ₹21,833 करोड़ के अनुबंध के तहत किया गया था। यह अनुबंध भारतीय नौसेना के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी युद्धपोत निर्माण सौदों में से एक है।

Key Points:-

(i) INS हिमगिरि को पहली बार 14 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। जहाज का नाम मूल INS हिमगिरि (F34) के नाम पर रखा गया है, जो एक लिफ्टर श्रेणी का फ्रिगेट था जिसे 2005 में सेवामुक्त कर दिया गया था। यह नाम भारतीय नौसेना की विरासत युद्धपोतों को सम्मानित करने की परंपरा को दर्शाता है।

(ii) भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा डिज़ाइन किया गया यह जहाज उन्नत स्टील्थ विशेषताओं और अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त है। यह एक संयुक्त डीजल या गैस (CODOG) प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित है जो प्रत्येक शाफ्ट पर लगे नियंत्रणीय पिच प्रोपेलर (CPP) को शक्ति प्रदान करती है।

(iii) यह जहाज 149 मीटर लंबा है, इसकी चौड़ाई 17.8 मीटर है और इसका विस्थापन 6,670 टन है। इसकी अधिकतम गति 28 नॉट (52 किमी/घंटा) है और इसकी मारक क्षमता 5,500 समुद्री मील है, जिससे भारतीय नौसेना की समुद्री परिचालन पहुँच में

वृद्धि होती है।

2. ISRO-NASA ने संयुक्त रूप से प्रथम दोहरे आवृत्ति पृथ्वी अवलोकन मिशन के लिए GSLV-F16 के माध्यम से NISAR उपग्रह का प्रक्षेपण किया।



30 जुलाई, 2025 को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) से GSLV-F16 रॉकेट के ज़रिए NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) उपग्रह का प्रक्षेपण किया। यह उन्नत पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं के लिए ISRO और NASA के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग का प्रतीक है।

- NISAR उपग्रह ISRO और NASA (राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन) के बीच पहला संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जिसमें कुल निवेश 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और विकास में एक दशक से अधिक समय लगा है।

- यह दुनिया का पहला रडार इमेजिंग उपग्रह है जिसे एक ही प्लेटफॉर्म पर दोहरे आवृत्ति वाले रडार बैंड - एल-बैंड और एस-बैंड - के साथ संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे पृथ्वी के क्रायोस्फीयर, पारिस्थितिक तंत्र और मिट्टी में होने वाले परिवर्तनों की सटीक निगरानी संभव हो सकेगी।

Key Points:-

(i) यह मिशन GSLV श्रृंखला का 18वां प्रक्षेपण था तथा भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण का उपयोग करते हुए 12वां प्रक्षेपण था, जिससे उच्च भार वाले पेलोड तैनात करने में ISRO की क्षमता में और वृद्धि हुई।

(ii) NISAR का प्राथमिक उद्देश्य 242 किलोमीटर क्षेत्र में उच्च-रिज़ॉल्यूशन, दिन-रात, सभी मौसम की इमेजिंग प्रदान करना है, हर 12 दिनों में उसी क्षेत्र का पुनरीक्षण करना और लगभग पूरी पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों को स्कैन करना है।

(iii) NISAR का वज़न लगभग 2,392 किलोग्राम है और यह लगभग 747 किलोमीटर की ऊँचाई पर सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षा में संचालित होगा। इसे 5 साल के मिशन जीवन के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसके उपभोग्य सामग्रियाँ लगभग 3 साल तक निरंतर संचालन में सहायक होंगी।

ENVIRONMENT

1. SERL शोधकर्ताओं द्वारा केरल में पहली बार तीन नई चींटी प्रजातियों की खोज की गई।



जुलाई 2025 में, क्राइस्ट कॉलेज, त्रिशूर (केरल) स्थित शदपदा एंटोमोलॉजी रिसर्च लैब (SERL) के शोधकर्ताओं ने केरल में पहली बार तीन नई चींटी प्रजातियों की खोज की—इंडोपालपेरिस पार्डस, पालपेरिस कॉन्ट्रारियस और स्टेनारेस हार्पिया, ये सभी

मायर्मेलियोन्टिडे परिवार से हैं। ये प्रजातियाँ केरल के पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं।

- यह खोज जर्नल ऑफ इन्सेक्ट बायोडायवर्सिटी एंड सिस्टेमेटिक्स में प्रकाशित हुई है और इसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)-भारत द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ये निष्कर्ष भारत के कीट जैव विविधता दस्तावेज़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- ये प्रजातियाँ केरल के विभिन्न जिलों, जैसे पथानामथिट्टा, इडुक्की, कोल्लम, कोझिकोड, मलप्पुरम और वायनाड में पाई गईं। इन्हें पहले अन्य भारतीय राज्यों में दर्ज किया गया था, लेकिन केरल में पहले कभी नहीं देखा गया था।

Key Points:-

(i) इंडोपालपेरस पार्डस मलप्पुरम जिले में पाया गया था और अपने बड़े आकार, चौड़े पंखों और तेंदुए जैसे धब्बों के लिए जाना जाता है। इसे पहले बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में देखा गया था।

(ii) पल्पेरस कॉन्ट्रारियस, जो पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मिज़ोरम में दर्ज किया गया था, केरल के कुट्टिकापुझा (कन्नूर), पयमथोडु (कोझिकोड) और थिरुनेली (वायनाड) जैसे क्षेत्रों में पाया गया। यह अपने चौड़े, आकर्षक पंखों और आकर्षक चिह्नों के लिए जाना जाता है।

(iii) स्टेनारेस हार्पिया, जो ईगल जैसे या हार्पी जैसे पंखों के लिए जाना जाता है, गवी (पठानमथिट्टा), वज़ाथोप (इडुक्की) और वट्टावडा में पाया गया था। इससे पहले, इस प्रजाति को केवल तमिलनाडु और तेलंगाना में प्रलेखित किया गया था।

Static GK

National Cooperative Development Corporation (NCDC)	प्रबंध निदेशक (MD) : पंकज कुमार बंसल	मुख्यालय: नई दिल्ली
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)	महानिदेशक (DG): डॉ. हिमांशु पाठक	मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना
MoD	मंत्री: राजनाथ सिंह	मुख्यालय: नई दिल्ली
Indian Navy (IN)	नौसेना प्रमुख (CNS) : एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी	मुख्यालय: नई दिल्ली
ISRO	अध्यक्ष: डॉ. वी. नारायणन	मुख्यालय: बेंगलुरु
Kerala	मुख्यमंत्री: पिनारई विजयन	राज्यपाल: राजेंद्र आर्लेकर
Ministry of Commerce and Industry (MoC&I)	केंद्रीय मंत्री: पीयूष गोयल	मुख्यालय: नई दिल्ली
Gujarat	मुख्यमंत्री: भूपेन्द्र पटेल	राज्यपाल: आचार्य देवव्रत
Myanmar	अंतरिम-	कार्यवाहक

	प्रधानमंत्री (PM) : यू न्यो साव	राष्ट्रपति : वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाईंग
Uttar Pradesh	मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ	राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल